



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, १७ जून, १९९५/२७ ज्येष्ठ, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-२, १९ मई, १९९५

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०)-४ (डी)-९/८८.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपमन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ५) की धारा ८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख २६ अक्टूबर, १९७१ के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या २-१४/७१-जी० ए० सी०, तारीख ७ नवम्बर, १९७१ द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश उपमन्त्री मोटर कार अग्रिम नियम, १९७१ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपमन्त्री (मोटर कार अग्रिम) (संशोधन) नियम, १९९५ है ।

2. नियम-4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश उपमन्त्री (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम-4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4 अधिकतम अग्रिम राशि.—मोटर कार के क्रय हेतु उप मन्त्री को अधिकतम राशि चार लाख रुपये या खरीदी जाने वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि उपमन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश उप मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1982 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया हो तो मोटर कार अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा उप मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ उप मन्त्री ने, उपाध्यक्ष या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति, की हैसियत में मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी” ।

आदेश द्वारा,

आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of Government Notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 19-5-95, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th May, 1995

No. GAD (PA) 4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 8-A of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 26th October, 1971 vide Notification No. 2-14/71-GAC, dated the 7th November, 1971, namely :—

1. **Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Amendment Rules, 1995.

2. **Amendment of Rule-4.**—For rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, the following shall be substituted, namely :—

“4 **Maximum amount of advance.**—The maximum amount which may be advanced to a Deputy Minister, for the purchase of a motor car shall not exceed rupees four lacs or the actual price of the motor car, which is intended to be purchased, whichever is less :

Provided that in case the Deputy Minister has taken the House Building Advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rules 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance

of Loan for House Building) Rules 1979; then, the total amount of the motor car advance together with the house building advance already availed of by the Deputy Minister shall not exceed the limit of four lacs rupees :

Provided also that where a Deputy Minister has taken the motor car advance in his capacity as the Deputy Speaker or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of motor car advance together with the motor car advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees”.

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मई, 1995

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-9/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15 नवम्बर, 1971 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या 2-12/71-जी० ए० सी०, तारीख 31 अगस्त, 1971 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अधिनियम) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अधिनियम) (संशोधन) नियम, 1995 है।

2. नियम-4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मन्त्री (मोटर कार अधिनियम) नियम, 1971 के नियम-4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4. अधिकतम अधिनियम राशि.—मोटर कार के क्रय हेतु मन्त्री को अधिकतम राशि चार लाख रुपये या खरीदी जाने वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अधिनियम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अधिनियम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अधिनियम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अधिनियम लिया हो तो मोटर कार अधिनियम की कुल राशि की परिसीमा मन्त्री द्वारा पहले से ही लिए गए भवन निर्माण अधिनियम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ मन्त्री ने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपमन्त्री या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति की हैसियत से मोटर कार अधिनियम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अधिनियम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।”

आदेश द्वारा,

आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of the Government notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated, the 19th May, 1995 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th May, 1995

No. GAD (PA) 4(D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the

Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 15th November, 1971 vide Notification No. 2-12/71-GAC, dated 31st August, 1971, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Amendment Rules, 1995.

2. *Amendment of rule-4.*—For rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, the following shall be substituted, namely:—

“4. **Maximum amount of advance.**—The maximum amount which may be advanced to a Minister for the purchase of a Motor Car shall not exceed rupees four lacs or the actual price of the motor car which is intended to be purchased, whichever is less ;

Provided that in case the Minister has taken the house building Advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979, then the total amount of motor car advance together with the house building advance already availed of by the Minister, shall not exceed the limit of four lacs rupees :

Provided also that where a Minister has taken the motor car advance in his capacity as the Speaker or the Deputy Speaker or the Deputy Minister or the Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of motor car advance together with the motor car advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees”.

By order,

Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग

(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 19 मई, 1995

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-9/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 अक्तूबर, 1971 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या 2-13/71-जी० ए० सी०, तारीख 7 सितम्बर, 1971 द्वारा प्रकाशित; हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) (संशोधन) नियम, 1995 है ।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मोटर कार अग्रिम) नियम, 1971 के नियम 4 के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“4 अधिकतम अग्रिम राशि.—मोटर कार को क्रय हेतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति; को अधिकतम राशि चार लाख रुपये या खरीदी जान वाली मोटर कार की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ;

परन्तु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, ने हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (भवन

निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1981 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश उप मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1982 के नियम 4 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1979 के नियम 4 के अधीन भवन निर्माण अग्रिम लिया हो तो मोटर कार अग्रिम की कुल राशि की परिसीमा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति द्वारा पहले लिए गए भवन निर्माण अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यथास्थिति, ने मन्त्री, उप मन्त्री या विधान सभा सदस्य, यथास्थिति, की हैसियत में मोटर कार अग्रिम ले रखा हो तो मोटर कार की कुल राशि की परिसीमा उसे पहले दिए गए मोटर कार अग्रिम सहित चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।”

आदेश द्वारा;

आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of Notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 19-5-95 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th May, 1995

GAD (PA) 4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated 15th October, 1971 vide Notification No. 2-13/71-GAC, dated the 7th September, 1971, namely ;—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Amendment Rules, 1995.

2. *Amendment of rule-4.*—For rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971, the following shall be substituted, namely :—

“4 **Maximum amount of advance.**—The maximum amount which may be advanced to the Speaker or Deputy Speaker as the case may be, for the purchase of a motor car, shall not exceed rupees four lacs or the actual price of the motor car which is intended to be purchased, whichever is less :

Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the house building advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 or under rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1979, then the total amount of the motor car advance together with the house building advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of four lacs rupees :

Provided also that where a Speaker or a Deputy Speaker, as the case may be, has taken the motor car advance in his capacity as the Minister or the Deputy Minister or the

Member of Legislative Assembly, as the case may be, the total amount of motor car advance together with the motor car advance already given to him shall not exceed the limit of four lacs rupees.

By order

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.